

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** के माह 04/2016 से माह 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक एवं श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.12.2017 से 15.12.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

- परिचयात्मक:-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपेश कुमार , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दया शंकर , वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.04.2016 से 07.05.2016 तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2014 से माह 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
- (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-** इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत / आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत / आ धिक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	Nil	Nil	86.44	61.66	24.78	3018.06	2960.45	57.61
2015-16	Nil	Nil	66.88	65.39	1.49	2534.273	2378.09	156.17
2016-17	Nil	Nil	74.65	70.71	3.94	2732.665	2550.58	182.08

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रु.लाख में)

योजना का नाम	2015-16			2016-17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन. एस. ए. पी)	Nil	295.80	277.14	18.66	390.11	361.26
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	11.75	11.75	Nil	98.34	98.33
अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	22.41	12.00	10.41	12.00	7.34
अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	5.74	2.61	3.13	8.53	1.02

(अ) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **...ब ...श्रेणी** की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:- सचिव, समाज कल्याण → निदेशक, समाज कल्याण → जिला समाज कल्याण अधिकारी

(ब)लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:- लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा गरीब, निर्बल, परितकता, निःशक्त, आरक्षित श्रेणी के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है ..(अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाए) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाए) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का **वश्लेषण** किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:- 1 शासन द्वारा निरस्त कार्य पर ₹ 16.77 लाख का निष्फल व्यय एवं ₹ 4.12 लाख की धनराश वगत 03 वर्षों से कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध रखना।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुवधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत वृत्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद में 23 निर्माण कार्यों के लिए ₹ 243.94 लाख का आवंटन प्रदान किया गया था। इन कार्यों में बारात घर, सी0सी0 मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक भवन आदि कार्य शामिल थे। शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि भूमि की उपलब्धता एवं योजना के भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही राश का आहरण किया जायेगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली के अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्यों के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई के पत्रांक सं0 मैमोंस कएस सी पी/2014-15 दिनांक 09 सितम्बर 2014 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था जिला पंचायत पोखरी को 02 कार्यों के लिए स्वीकृत धनराश ₹ 33.54 लाख के सापेक्ष प्रथम कस्त के रूप में ₹ 16.77 अवरुद्ध किये गये। ववरण निम्न है:-

(धनराश लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत धनराश	अवरुद्ध धनराश
1.	देवर में अनुसूचित जाति बस्ति देवर तल्ला से बुखलीधार तक तक खड़जा सी0सी0, रे लंग मार्ग निर्माण	14.36	7.18
2.	देवर में अनुसूचित जाति बस्ति देवर पल्ला में देवरखाल से बंडरमेक तक तक अनु0 जाति बस्ती में मार्ग निर्माण	19.18	9.59
	योग	33.54	16.77

उक्त कार्यों के संदर्भ में शासन के पत्रांक सं0 1550/XXIV/14-11(13)/2014 दिनांक 24 सितम्बर 2014 द्वारा उपरोक्त कार्य के प्रगति के सम्बन्ध में इकाई की आख्या चाही गयी थी। उक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 2017 को शासन को अवगत कराया कि निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को 50 प्रतिशत धनराश अवरुद्ध की जा चुकी है परन्तु वर्तमान तिथि तक कार्य पर किया गया व्यय शून्य है। इसी क्रम में शासन द्वारा एक अन्य शासनादेश सं0 1674/XVII-4/2014-11(13) दिनांक 01 अक्टूबर 2014 को, उक्त कार्य निरस्त करते हुए कार्य की समस्त धनराश ₹ 33.54 लाख को तत्काल राजकोष में जमा करने के आदेश दिये गये। सम्प्रेक्षा अवधि (11/17) तक

धनराश शासन को प्रेषित नहीं किया जा सकी थी। संज्ञान में आया कि शासन द्वारा जो 02 कार्य निरस्त किये गये थे की अवमुक्त धनराश ₹ 16.77 लाख कार्यदायी संस्थान (नगर पंचायत पोखरी) द्वारा व्यय किया जा चुका था। जब कि शासन को, जब इकाई द्वारा कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की गयी थी तो समस्त अवमुक्त धनराश ₹ 16.77 लाख का कार्यदायी संस्था के पास उपलब्ध थी। इकाई द्वारा शासन से कार्य निरस्त होने की दशा में अवलम्ब धनराश कार्यदायी संस्था से प्राप्त की जानी चाहिए थी। जब कि इकाई द्वारा शासन से कार्यों की निरस्त की सूचना कार्यदायी संस्था को पत्रांक संख्या 1646-48/स0क0एस0सी0पी0/2014-15 दिनांक 28 अक्टूबर 2014 को अर्थात् शासनादेश जारी होने के 28 दिनों के पश्चात् प्रेषित किया गया जो कि वभागीय श्रथलता को दर्शाता है। अतः शासन द्वारा स्वीकृत कार्य पर ₹ 16.77 निरर्थक व्यय से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है एवं अवशेष धनराश ₹ 16.77 लाख इकाई स्तर सम्प्रेक्षा अवध (11/17) तक अवरुद्ध पड़ी है। परिणाम स्वरूप उक्त दोनों निर्माण कार्य पर धनराश ₹ 16.77 लाख का किया गया व्यय निरर्थक है चूँकि निर्माण कार्य अधूरे पर ही छूटा है।

शासनादेशानुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित के पश्चात् ही कार्यदायी संस्था को धनराश अवमुक्त किया जाना चाहिए था। जाँच में पाया गया कि बिना भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही धनराश ₹ 4.12 लाख कार्यदायी संस्था (खण्ड विकास अधिकारी दशोली) को अवमुक्त कर दी गयी थी जो 03 वर्षों से कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्ध पड़ी है। ऐसे कार्य का ववरण निम्न है:-

(धनराश लाखों में)

क्र०सं०	योजना का ववरण	स्वीकृत धनराश	आवंटन धनराश
1.	अनुसूचित जाति बस्ति में बरातघर निर्माण सोनला	8.24	4.12
	योग	8.24	4.12

उक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि कार्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था नगर पंचायत पोखीर को वापस किये जाने सम्बन्ध में पत्राचार किया गया था। किन्तु निर्माण इकाई द्वारा अवगत कराय गया कि प्रेषित धनराश को उनके द्वारा व्यय किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप धनराश को वापस किया जाना सम्भव नहीं है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा कार्य निरस्त की जानकारी कार्यदायी संस्था को शासनादेश जारी होने के 28 दिन के बाद प्रेषित किया गया था जो कि पूर्णता इकाई की लापरवाही है। यदि कार्यदायी संस्था को उल्लेखित कार्य का निरस्त करने संबंधी जानकारी समयान्तर्गत किया गया होता तो कार्यों पर ₹ 16.77 लाख के निष्फल व्यय से बचा जा सकता था एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना धनराश अवमुक्त करने के संदर्भ में इंगित करने पर इकाई ने कहा कि अवमुक्त धनराश वापस किये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से पत्राचार किया जा रहा है उत्तर

सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार बिना भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त नहीं किया जाना चाहिए था।

अतः शासन द्वारा निरस्त कार्य पर ₹ 16.77 लाख का निष्फल व्यय एवं ₹ 4.12 लाख की धनराशि वगत 03 वर्षों से कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्ध रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:2. निर्धारित आयु सीमा पूर्ण किये बिना वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने तथा धनराशि रु0 2.01 लाख का अदेय भुगतान किया जाना।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पुरुष अथवा महिला को वृद्धावस्था पेंशन राज्य एवं केन्द्र द्वारा सम्मिलित रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी श्रोतों से मासिक आय न्यूनतम 4000 मासिक से अधिक न हो तथा जिनके 20 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुत्र की भी आय का कोई साधन न हो, को प्रदान किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान जनवरी 2014 से पूर्व रु0 400 प्रतिमाह, जनवरी 2014 से रु0 800 प्रतिमाह तथा जून 2016 से रु0 1000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत विभागीय कार्मिकों द्वारा माह मई 2016 में किये गये लाभार्थियों के सत्यापन सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा 04 लाभार्थियों के आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि के अनुसार जिनकी आयु वर्तमान में भी 60 वर्ष से कम है, को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किया गया था तथा उनको पेंशन स्वीकृति के माह से लगातार पेंशन का भुगतान किया गया था। विवरण निम्नवत् है;

क्रम सं०	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी संख्या	जन्म तिथि	पेंशन स्वीकृति का माह	माह तक किया गया भुगतान	अधिक भुगतानित माह की संख्या	अनियमित भुगतानित पेंशन की राशि
1	बसन्ती देबी/राम सिंह	CHM-RO 405/6616	01.01.1960	04/2012	09/2017	78	52400
2	रेवती देबी/पुष्कर सिंह	CHM-RO 405/7529	01.01.1957	04/2012	12/2016	69	43400
3	हेमा देबी/मोहन सिंह	CHM-RO 405/6612	01.01.1958	04/2012	09/2017	78	52400
4	रमेश चन्द्र/शोभा राम	CHM-RO 405/17589	24.04.1965	04/2012	09/2017	78	52400
	कुल योग						200600

उपरोक्त तालिका में वर्णित लाभार्थियों के सत्यापन के दौरान प्रस्तुत आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति के लिए निर्धारित आयु सीमा कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, से कम पायी गयी। परन्तु इन लाभार्थियों को निर्धारित आयुसीमा से पूर्व ही पेंशन स्वीकृत किया गया था तथा उनको पेंशन के रूप में धनराशि रु0 2.01 लाख का अदेय भुगतान किया गया था। यह भी पाया गया कि इन लाभार्थियों को वर्तमान में भी पेंशन किस्त का भुगतान किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि इन लाभार्थियों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिवार रजिस्टर में अंकित जन्मतिथि के आधार पर पेंशन स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि के अनुसार उम्र कम होने की स्थिति में निदेशालय स्तर से पत्राचार कर दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

अतः वृद्धावस्था पेंशन मद में निर्धारित आयु पूर्ण किये बिना वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने तथा धनराशि रु0 2.01 लाख का अदेय भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:-3 राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय छात्रावास में भोजन व्यवस्था पर ₹ 2.39 लाख का अनियमित व्यय।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी शासनादेश (जनवरी/2009) में स्पष्ट प्रावधान है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न आश्रम पद्धति विद्यालय तथा 25 एवं उससे अधिक संवा सयों/संवा सनियों की समस्त आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था निवदा के आधार पर Outsource के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है एवं निवदा की अवधि एक वर्ष रखी जायेगी तथा निवदा हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं अन्य नियमों का कटोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली के लेखा भलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा संचालित आवासीय राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय छात्रावास चमोली में वर्ष 2017-18 में छात्रों की संख्या 48 है। जिसके लिए नियमानुसार निवदा के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया। विद्यालय में भोजन व्यवस्था पर पूर्व स्वीकृत निवदा वर्ष 2016-17 (मैसर्स मैट्रिक इन्वायरमेंटल राजेशवरपुरम श्यामपुर ऋषिकेश) के पूर्व स्वीकृत दर पर ही वर्ष 2017-18 में भी छात्रावास में भोजन की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में भोजन व्यवस्था पर सम्प्रेक्षा अवधि (11/2017) ₹ 2.39 लाख का अनियमित धनराश व्यय किया गया है। शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि निवदा की अवधि केवल एक वर्ष रखी जायेगी। शासनादेश अनुसार वृत्तीय वर्ष 2017-18 के लिए छात्रावास हेतु भोजन व्यवस्था पर निवदा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति करने पर इकाई ने कहा कि वर्ष 2017-18 में भोजन व्यवस्था हेतु निदेशालय के आदेशानुसार वर्ष 2016-17 हेतु आमंत्रित निवदा के आधार पर भोजन व्यवस्था ठेकेदार के माध्यम से संचालित की जा रही है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था निवदा के आधार पर Outsource के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है एवं निवदा की अवधि एक वर्ष रखी जायेगी। जबकि निवदा अवधि समाप्त होने के पश्चात भी छात्रावास के लिए भोजन की व्यवस्था संस्था द्वारा की जा रही है। जो कि शासनादेश की अवहेलना है।

अतः राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय छात्रावास में भोजन व्यवस्था पर ₹ 2.39 अनियमित व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर: 4 अम्बेडकर भवन निर्माण कार्य के आगणन पर बिना अनुमोदन प्राप्त किये कार्य प्रारम्भ किये जाने तथा धनराशि रु0 76.92 लाख का व्यय किये जाने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण न किया जाना।

शासन द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास योजना के अन्तर्गत एक अम्बेडकर भवन, जिसकी लागत ` 1.00 करोड के भीतर हो, निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में स्वीकृत किया गया था। निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्माण कार्य हेतु माह फरवरी 2011 में ` 38.96 लाख एवं सितम्बर 2011 में ` 38.96 लाख कुल धनराशि ` 76.92 लाख निर्गत की गयी थी। अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन के निर्माण का उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मार्केटिंग व्यवस्था, शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र, ठहरने की व्यवस्था, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोष्ठी तथा कॉन्फ्रेन्स हाल आदि के लिए किया जाना था। आवंटन पत्र में यह निर्देशित किया गया कि उक्त भवन के निर्माण हेतु माडल आगणन तैयार कर निदेशक, समाज कल्याण से अनुमोदन उपरान्त ही डा0 भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को अधिकतम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाए।

सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि भवन निर्माण के लिए आवंटित सम्पूर्ण धनराशि का आहरण कर मार्च 2011 एवं नवम्बर 2011 में कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, चमोली को उपलब्ध करा दी गयी थी। जिलाधिकारी के पत्र दिनांक फरवरी 2013 तथा निर्देशों के क्रम में सिंचाई खण्ड द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण निर्माण की धनराशि अन्य कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, गोपेश्वर को उपलब्ध करा दिया गया था। तदुपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा अम्बेडकर भवन निर्माण हेतु ` 92.58 लाख का आगणन वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी। पुनः निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2013 के माध्यम से संशोधित आगणन ` 99.85 लाख को शासन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया था। परन्तु शासन का अनुमोदन वर्तमान तक अप्राप्त है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति प्रतिवेदन की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य अक्टूबर 2013 में प्रारम्भ किया गया था तथा माह जुलाई 2015 तक उपलब्ध धनराशि ` 76.92 लाख का व्यय किया जा चुका था तथा भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत तक थी। निर्माण कार्य विगत 02 वर्ष से भी अधिक समय से बन्द पडा था। अतः अधूरे निर्माण कार्य के इतने अधिक दिनों तक बन्द होने से निर्माण कार्य के दिन प्रति दिन जर्जर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। डा0 भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य वर्तमान तक पूर्ण नहीं हो पाया

था जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की जनता को इन भवनों से होने वाले लाभो से वंचित रहना पड रहा है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि वर्तमान में आगणन के अनुमोदन सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पा रहे है। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से सम्पर्क कर यथास्थिति से अवगत कराया जाएगा। यह भी अवगत कराया कि प्रस्तुत आगणन के अनुसार धनराशि कम आवंटित होने के कारण वर्तमान तक भवन निर्माण पूर्ण नहीं किया जा सका है। इकाई का उत्तर सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता क्योंकि निर्माण कार्य की किसी भी आगणन पर सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

अतः निर्माण कार्य के आगणन पर बिना अनुमोदन प्राप्त किये कार्य प्रारम्भ किये जाने तथा धनराशि रु0 76.92 लाख का व्यय किये जाने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर: 5 कार्यालय द्वारा बैंक खातों में रु0 460.21 लाख की धनराशि के अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या; 875(1)/वित्त अनुभाग-3/ 2003-04 दिनांक 30 अप्रैल 2003 एवं पत्र संख्या: 99/xxvii(14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यों हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्राप्त न की गयी हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी एल ए में रखी जाय तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखा शीर्षक 0049 में जमा कर दिया जाय। यह भी वर्णित है कि जब किसी कार्य के लिए तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाय।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली की रोकड बही एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 02 बैंक खातों का संचालन अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था, जिसके संचालन के लिए उपरोक्त प्रावधानानुसार शासन के वित्त विभाग से कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी है। योजनाओं के अन्तर्गत शासन/निदेशालय स्तर से आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित कर इस बैंक खातों में रखा जाता है। आगे जाँच में पाया गया कि अधिकतर योजनाओं में आवंटित धनराशि को प्रगति प्रतिवेदनों में सत्प्रतिशत व्यय दर्शाया गया जबकि विगत दो वर्षों में बैंक से प्राप्त किये गये विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में निम्नानुसार धनराशि पडी हुई थी :

(धनराशि ` लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	03/2016 के अन्त में अवशेष धनराशि	03/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि	11/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि
1	State Bank of India	11272220140	999.29	849.83	455.61
2	State Bank of India	35576838946	43.79	275.02	4.60
	Total		1043.08	1124.85	460.21

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा तिथि माह 11/2017 के अन्त में भी उक्त बैंक खाते में रु0 460.21 लाख की धनराशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध पडी थी। यह भी पाया गया कि इन बैंक खातों से किये जा रहे लेन-देनों के लिए रोकड बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा था। यह भी पाया गया कि योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित एवं कोषागार से आहरित सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को शतप्रतिशत धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा रहा था जबकि बैंक विवरणी के अनुसार उक्त योजनाओं में वर्ष के अन्त में धनराशि शेष पडी हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि शासन को मिथ्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि बैंक खाते में अवशेष धनराशियों में अनुसूचित जाति उपयोजना की रू0 1.50 करोड तथा शेष वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन आदि योजनाओं से सम्बन्धित है जिसे लाभार्थियों को भुगतान किया जाना है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति उपयोजना की वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित धनराशि है जिसे दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम छः माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था तथा सभी पेंशन योजना की धनराशि सीधे कोषागार के माध्यम से आनलाईन भुगतान किया जाता है। अतः बैंक खाते में धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः कार्यालय द्वारा बैंक खातों में रू0 460.21 लाख की धनराशि के अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर :6 विकलागं पेन्शन रू 195.00 लाख अनियमित प्रेषण ।

विकलाग पेशन हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जो बी०पी०एल श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। जिसकी मासिक आय रू 4000/- से अधिक न हो एवं एक परिवार में पति पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पेशन का लाभ मिलेगा एवं महिला लाभार्थि को प्राथमिकता दी जायेगी। पेशन का भुगतान प्रतिमाह रू 1000/- की दर से त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाता है। निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड के पत्रांक सख्या 5137 दिनांक 29 मार्च 2017 में स्पष्ट प्रावधान था कि निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार पेशन की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में आनलाईन/डी०बी०टी के माध्यम से भुगतान किये जाना का प्रावधान है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी के वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (11/2017) तक के विकलागं भरण पोषण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कुल रू 669.87 लाख विकलाग पेशन हेतु अवमुक्त किये गये थे। जाँच में पाया गया कि योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि में 6876 पेशनरों को रू. 195.00 लाख आफ लाईन वितरण किया गया। जो कि आदेशों कि अवहेलना है। जबकि उच्चधिकारी द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश दिये थे कि समस्त धनराशि का भुगतान आनलाईन किया जाये। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने कहा कि विकलाग पेशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के द्वारा डाकघर में खोले गये खातों के माध्यम से धनराशि का भुगतान आफ लाइन के माध्यम से किया जा रहा है। भवष्य में उक्त खातों को सी.बी.एस. खातों में हस्तांतरण हेतु कार्यवाही की जा रही है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार पेशन की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में आनलाईन/डी० बी०टी के माध्यम से भुगतान किया जाना का प्रावधान है। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया है।

अतः विकलागं पेन्शन रू 195.00 लाख अनियमित प्रेषण करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर : 1 विगत दो वर्षों से कोषागार से ₹ 76.12 लाख के आहरण के उपरांत भी कार्यालय द्वारा रोकड़ बही में इन्द्राज न किया जाना ।

कोषागार के माध्यम से समस्त शासकीय भुगतान सीधे संबंधितों के बैंक खातों में अंतरण कर ई-पेमेंट प्रणाली को लागू किये जाने से सम्बंधित उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के दिशानिर्देश दिनांक 01/2013 के बिंदु सं 4.9 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से ekosh.uk.gov.in पर अपने Login ID से अपने देयको की धनराशि संबंधितों के बैंक खातों में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित विवरण 11-सी पंजिका, केश बुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थल पर करेंगे ।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा की कार्यालय द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सैकोट द्वारा विगत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आहरित कुल धनराशि ₹ 7612116=00 को शासनादेश का उल्लंघन कर रोकड़बही में इन्द्राज नहीं किया गया जो की निम्नवत है :-

वर्ष	आवंटित धनराशि	आहरित धनराशि	ब्यय धनराशि	समर्पण	रोकड़ बही में इन्द्राज न किये गये धनराशि
2016-17	4180000	4040393	4040393	139607	4040393
2017-18 (Nov'17)	5377200	3571723	3571723	Nil	3571723
				Total	7612116

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा सहमति प्रदान करते हुए बताया गया की जानकारी के अभाव में ई-पेमेंट से सम्बंधित लेनदेन को रोकड़ वही में इन्द्राज नहीं किया गया एवं भविष्य में अनुपालन किया जायेगा ।

अतः राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सैकोट द्वारा विगत दो वर्षों से कोषागार से ₹ 76.12 लाख आहरण के उपरांत भी रोकड़ बही में इन्द्राज न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग-दो अ प्रस्तर सं०	भाग-दो ब प्रस्तर सं०	STAN प्रस्तर सं०
59	2007-08	01 से 03	01 से 07	शून्य
130	2008-09	शून्य	01	शून्य
59	2011-12	01	01,02	01,02
11	2016-17	शून्य	01,02	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तारों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया कि संदर्भित प्रस्तर की अनुपालन आख्या पूर्व में निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित किया गया है एवं वर्तमान स्थिति को लेते हुए महालेखाकार कार्यालय के लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया गया को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग-4
इकाई के सर्वोत्तम कार्य
शून्य

भाग-5

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(अ) शून्य

सतत अनियमितताएं:-

(अ) शून्य

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री बृज लाल पलेठा	जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	श्री सुरेन्द्र लाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र